

एफ. सं. 370142/22/2024 - टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

दिनांक: 16 दिसंबर, 2024

विषय: प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के प्रावधानों पर मार्गदर्शन संबंधी व्याख्या 2/2024- संबंधित।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (जिसे आगे 'डीटीवीएसवी योजना, 2024' या 'योजना' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद समाधान प्रदान करने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के अध्याय IV के माध्यम से अधिनियमित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, जो आयकर मुकदमेबाजी लंबित पड़ी हैं उन्हें कम करना, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और करदाताओं को मानसिक शांति, निश्चितता और समय और संसाधनों की बचत प्रदान करके लाभान्वित करना है, जो अन्यथा लंबी और अव्यवस्थित मुकदमेबाजी प्रक्रिया पर खर्च होते हैं।

2. उक्त योजना की प्रारंभ तिथि 1.10.2024 पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और प्रपत्र भी 20.09.2024 को अधिसूचित किए गए हैं। डीटीवीएसवी योजना, 2024 के अधिनियमित होने के बाद, हितधारकों से इसमें निहित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शन मांगने के लिए कई प्रश्न प्राप्त हुए थे।

3. तदनुसार, डीटीवीएसवी योजना, 2024 की धारा 97 के तहत, जो बोर्ड को सार्वजनिक हित में दिशा निर्देश या अनुदेश जारी करने का अधिकार देती है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर के रूप में परिपत्र संख्या 12/2024 दिनांक 15.10.2024 मार्गदर्शन संबंधी व्याख्या 1/2024 के माध्यम से जारी किया गया था। हालाँकि, स्पष्टीकरण के लिए हितधारकों से कई अन्य प्रश्न मिले हैं। इस प्रकार, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर के रूप में मार्गदर्शन संबंधी व्याख्या 2/2024 को एतद्वारा और अधिक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। यह योजना के प्रावधानों के संबंध में बेहतर जागरूकता और समझ पैदा करने में कर-दाताओं के लिए सहायक होगा।

4. वर्तमान मार्गदर्शन व्याख्या 2/2024 में, मार्गदर्शन व्याख्या 1/2024 के एफएक्यू संख्या 8 को संशोधित किया गया है और एफएक्यू संख्या 36 के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, मार्गदर्शन व्याख्या 1/2024 के एफएक्यू संख्या 8 को हटा दिया गया माना जाएगा।

क्र. सं.	मुद्दा	टिप्पणियाँ
मामलों की पात्रता		
36.	मान लीजिए कि कोई करदाता डीटीवीएसवी योजना, 2024 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, क्योंकि उसकी अपील 22.7.2024 से लंबित है। लेकिन बाद में, इससे पहले कि करदाता डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत घोषणा दाखिल कर सके, उसकी अपील को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित कर दिया	हां, ऐसे मामले योजना के तहत निपटान के लिए पात्र हैं, क्योंकि अपील 22.7.2024 तक लंबित थी। विवादित कर की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि 22.7.2024 को लंबित अपील निस्तारित होना बाकी है।

	गया है या योजना के प्रयोजनों के लिए वापस ले लिया गया है। क्या ऐसा करदाता अब भी योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल कर सकता है?	
37.	मान लीजिए कि एक करदाता ने प्रपत्र - 1 में एक घोषणा की है। घोषणा के बाद, अपील का निपटारा संबंधित प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है। क्या ऐसा मामला निपटान के लिए पात्र है?	हाँ, ऐसा मामला निपटान के पात्र है।
38.	अपील दाखिल करने की समय सीमा 22 जुलाई 2024 से पहले समाप्त हो गई है, लेकिन देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ अपील 22 जुलाई 2024 के बाद दायर की गई है। क्या करदाता ऐसे मामले में योजना का विकल्प चुन सकता है?	नहीं, किसी करदाता द्वारा योजना का विकल्प चुनने के लिए अपील 22 जुलाई, 2024 तक लंबित होनी चाहिए। इस प्रकार, जहां देरी की माफी के आवेदन के साथ अपील 22 जुलाई, 2024 के बाद दायर की जाती है, तो 22 जुलाई, 2024 को अपील के विलंबित होने के समान नहीं है। तदनुसार, ऐसे मामले पात्र नहीं होंगे।
39.	मान लीजिए कि देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ 22 जुलाई, 2024 से पहले एक ऐसी अपील दायर की गई है, जो 22 जुलाई, 2024 से पहले भी दायर की गई है। योजना के तहत घोषणा की तारीख से पहले देरी को माफ़ करने की अनुमति देते हुए इस अपील को स्वीकार कर लिया गया है। क्या ऐसा कोई करदाता इस योजना का विकल्प चुन सकता है?	हां। ऐसे मामलों में जहां अपील के साथ-साथ माफी आवेदन 22 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर किया गया है। क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर ऐसे मामले 22 जुलाई 2024 को लंबित अपील में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए, करदाता ऐसे मामलों में योजना के तहत निपटान का विकल्प चुन सकता है।
40.	1.4.2021 से पहले की गई खोज कार्रवाई के मामले में, खोज वर्ष के अलावा अन्य पिछले वर्षों का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 153क या 153ग के तहत किया गया है, और खोज के वर्ष के लिए मूल्यांकन अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत किया गया है। क्या इनमें से कोई भी मूल्यांकन आदेश डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत शामिल किया जा सकता है?	नहीं, ऐसे मामलों को डीटीवीएसवी योजना, 2024 की धारा 96(क)(i) के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
41.	क्या अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना के खिलाफ दायर की गई अपील और 22 जुलाई 2024 तक लंबित अपील डीटीवीएसवी योजना, 2024 के लिए पात्र है?	हां। अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना के खिलाफ दायर की गई कोई भी अपील और 22 जुलाई, 2024 तक लंबित कोई भी अपील योजना के तहत निपटान के लिए पात्र है।
42.	आईटी अधिनियम की धारा 248 कुछ मामलों में कर कटौती के दायित्व से इनकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील से संबंधित है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती है जहां 1.4.2022 को या उसके बाद केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान किया जाता है। क्या अधिनियम की धारा 248 के तहत 1.4.2022 से पहले दायर की गई अपील डीटीवीएसवी योजना, 2024 के लिए पात्र है?	हां।
43.	जहां अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में	हां। डीटीवीएसवी योजना, 2024 की धारा 96 में स्पष्ट रूप

	निर्दिष्ट किसी समझौते के तहत जानकारी प्राप्त की गई है; हालाँकि, ऐसी जानकारी का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन आदेश में कुछ जोड़ने के लिए 'इस्तेमाल' नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में, क्या निर्धारिती डीटीवीएसवी योजना, 2024 का विकल्प चुन सकता है?	से कहा गया है कि यह योजना वहां लागू नहीं होगी जहां कर बकाया अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर किए गए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। तदनुसार, जहां धारा 90 या धारा 90क के तहत प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन आदेश में कुछ जोड़ने के लिए नहीं किया गया है, निर्धारिती ऐसे आदेशों के लिए योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
44.	जहां उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों के समक्ष समीक्षा याचिकाएं लंबित हैं, क्या वे मामले डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत निपटान के लिए पात्र हैं?	नहीं। समीक्षा याचिका का लंबित रहना किसी अपील के लंबित होने के समान नहीं है। इसलिए, भले ही 22 जुलाई, 2024 तक कोई समीक्षा याचिका लंबित हो, इसे अपील की लंबितता नहीं माना जाएगा।
45.	क्या डीटीवीएसवी योजना, 2024 का लाभ ऐसे मामले में लिया जा सकता है जहां कार्यवाही आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष लंबित है या जहां आईटीएससी के आदेश के खिलाफ रिट दायर की गई है?	नहीं
46.	यदि जहां करदाता या विभाग ने धारा 158क/158कक/158कख के तहत घोषणा/आवेदन दाखिल किया है, वे डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत पात्र हैं?	हां। ऐसे मामलों में, जहां 22 जुलाई, 2024 को या उससे पहले अधिनियम की धारा 158क 58कक/1 58कख के तहत घोषणा/आवेदन दायर किया गया है, करदाता योजना के तहत निपटान का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते कि यदि संबंधित वर्ष से संबंधित कोई अपील है, तो उसका भी निपटारा किया गया हो।

अलग रखी गई अपील :

47.	अपील को आईटीएटी / सीआईटी (क) / डीआरपी से अलग रखा गया और 22.07.2024 को लंबित थी। क्या, ऐसे मामलों में निर्धारिती इस योजना का विकल्प चुन सकता है?	मार्गदर्शन व्याख्या 1/2024 के एफएक्यू नंबर 24 का संदर्भ लें। इसमें उल्लेख किया गया था कि- "योजना के अनुसार, एक अपील जो 22.7.2024 तक लंबित है, वह निपटान के लिए पात्र होगी। एओ के लिए एक अलग मामला इस तरह से लंबित अपील नहीं है। इसलिए, एओ से अलग मामले चाहे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है या आंशिक रूप से अलग रखा गया है योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।" हालाँकि, जहां किसी अपील को आईटीएटी/सीएलटी(ए)/डीआरपी से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, ऐसी अपीलें निपटान के लिए पात्र होंगी। साथ ही, जहां किसी अपील को आईटीएटी/सीआईटी(ए)/डीआरपी से आंशिक रूप से अलग कर दिया गया है, वहां जिन सभी मुद्दों को अलग रखा गया है, वे एक अलग अपील होंगी और निपटान के लिए पात्र होंगे और विवादित कर की गणना इस तरह की जाएगी जैसे कि यह उस स्तर पर लंबित है, जिस पर इसे अलग रखा गया है।
-----	---	--

अभियोग पक्ष

48.	जहां अभियोजन की कार्यवाही अभी तक अदालत के समक्ष दायर नहीं की गई है, क्या निर्धारिती इस योजना के लिए पात्र है?	हां। डीटीवीएसवी योजना, 2024 की धारा 96 का संदर्भ लिया जा सकता है। उक्त योजना की धारा 96(क) (ii) के प्रावधानों के अनुसार, यह योजना उस मूल्यांकन वर्ष से संबंधित कर बकाया के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके संबंध में घोषणा दाखिल करने की तारीख पर या उससे पहले अभियोजन शुरू किया गया है। तदनुसार, जहां
-----	---	---

		अभियोजन कार्यवाही अभी तक अदालत के समक्ष दायर नहीं की गई है, करदाता इस योजना का विकल्प चुन सकता है।
49.	यदि अभियोजन एक अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए है और अपील एक अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए है, तो क्या इससे निर्धारिती को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा?	नहीं, धारा 96(क)(ii) मूल्यांकन वर्ष से संबंधित ऐसे मामलों पर रोक लगाती है जिसके संबंध में घोषणा दाखिल करने की तारीख पर या उससे पहले अभियोजन स्थापित किया गया है। इस प्रकार, एक मूल्यांकन वर्ष में अभियोजन निर्धारिती को किसी अन्य मूल्यांकन वर्ष के लिए घोषणा दाखिल करने से नहीं रोकता है, यदि वह अन्यथा पात्र है।
देय राशि की गणना		
50.	डीटीवीएसवी योजना, 2024 अलग-अलग दरों का प्रावधान करती है जहां घोषणा 31.12.2024 को या उससे पहले दाखिल की जाती है और जहां यह 1.1.2025 को या उसके बाद दाखिल की जाती है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या निचली दर की प्रयोज्यता के लिए विवादित राशि का भुगतान भी 31.12.2024 से पहले किया जाना आवश्यक है?	डीटीवीएसवी नियम, 2024 के साथ पढ़ी गई योजना के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है। डीटीवीएसवी नियम, 2024 के नियम 3 के अनुसार, देय राशि घोषणा दाखिल करने की तारीख से जुड़ी हुई है। तदनुसार, जहां घोषणा 31.12.2024 को या उससे पहले दायर की जाती है, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 की धारा 90 में निर्दिष्ट तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित होगी। हालाँकि, जहां घोषणा 1.1.2025 को या उसके बाद दायर की जाती है, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि उक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होगी। विवादित राशि का भुगतान डीटीवीएसवी योजना की धारा 92(2) के अनुसार यानी प्रपत्र से 2 में प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।
51.	क्या विवादित कर की गणना करते समय अपील के संबंध में दायर किए गए किसी अतिरिक्त आधार पर विचार किया जाना चाहिए?	यदि 22 जुलाई, 2024 को या उससे पहले कोई अतिरिक्त आधार दिया गया है, तो इसे विवादित कर की गणना के उद्देश्य से माना जाएगा।
विवादित जुर्माना		
52.	मान लीजिए करदाता द्वारा संबंधित क्रांटम अपील के निपटान के लिए घोषणा दायर करने के बाद जुर्माना लगाया गया है। ऐसे मामले में, क्या क्रांटम अपील के कर बकाया का निपटान करने पर, ऐसे कर बकाया के संबंध में जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा?	योजना की धारा 89(1)(ण) में कर बकाया की परिभाषा का संदर्भ लिया जा सकता है। कर बकाया में वसूले जाने वाला ब्याज या वसूला गया ब्याज और लगाए जाने वाला या लगाया गया जुर्माना शामिल है। हालाँकि, क्रांटम अपील का निपटान विवादित कर के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, जहाँ विवादित कर का अर्थ अधिभार और उपकर सहित आयकर है। इस प्रकार, क्रांटम अपील के निपटान के लिए विवादित कर में लगाए जाने वाले या लगाए गए जुर्माने को शामिल नहीं किया जाता है। तदनुसार, क्रांटम अपील के निपटान पर, नामित प्राधिकारी योजना के तहत निपटान किए गए कर बकाया के संबंध में लगाए जाने वाले या लगाए गए जुर्माने से छूट प्रदान करेगा।
53.	मान लीजिए किसी मामले में, मूल्यांकन में किए गए परिवर्धन अंतिम रूप तक पहुंच गए हैं। 22 जुलाई, 2024 तक कोई भी क्रांटम अपील लंबित नहीं है। हालाँकि,	ऐसा जुर्माना जो क्रांटम परिवर्धन से असंबंधित है, स्पष्ट रूप से निपटान के लिए पात्र है, जहां ऐसे जुर्माने के संबंध में अपील 22 जुलाई, 2024 तक लंबित है। ये जुर्माने क्रांटम परिवर्धन से असंबंधित हैं और इसलिए क्रांटम

	जुर्माना अपील 22 जुलाई, 2024 तक लंबित है, जो उक्त मूल्यांकन आदेश में किए गए परिवर्धन से संबंधित है। क्या किसी जुर्माना अपील का निपटारा क्रांतिम अपील से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है	अपीलों से स्वतंत्र रूप से निपटाया जा सकता है। इसके अलावा, जहां मूल्यांकन में किए गए परिवर्धन अंतिम रूप तक पहुंच गए हैं और इस प्रकार 22 जुलाई, 2024 तक कोई क्रांतिम अपील लंबित नहीं है, निर्दिष्ट तिथि यानी 22 जुलाई, 2024 तक कोई विवादित आय या विवादित कर नहीं है। इसलिए, इस तरह के जुर्माने को योजना की धारा 90 में तालिका की क्रम संख्या (ग) और (घ) के अनुसार अलग से निपटाया जा सकता है।
54.	क्या ऐसे जुर्माने के विरुद्ध अपील, जो परिमाण निर्धारण से संबंधित नहीं हैं, जैसे अधिनियम की धारा 271ख, 27खक, 271घक के तहत जुर्माना, इत्यादि, विवादित कर से संबंधित अपील के निपटारे पर माफ़ कर दिए जाते हैं?	नहीं, ऐसे जुर्माने के आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा अलग से किया जाना आवश्यक है।
एपीए/एमएपी मामले		
55.	एपीए/एमएपी के मामले में, क्या गैर-एपीए/एमएपी समायोजन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए योजना का विकल्प चुना जा सकता है?	इस योजना में विवाद को पूर्ण रूप से निपटाने की परिकल्पना की गई है। यह योजना आंशिक रूप से मुद्दों को निपटाने की परिकल्पना नहीं करती है। इसलिए, लंबित अपील में जो भी मुद्दे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से निपटाया जाना चाहिए, चाहे वे एपीए/एमएपी समायोजन से संबंधित हों या अन्यथा।
घोषणा पत्र दाखिल करने से पहले चुकाया गया कर		
56.	क्या विवादित कर के विरुद्ध भुगतान किए गए पिछले करों का क्रेडिट डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध उपलब्ध होगा?	हां। घोषणा दाखिल करने से पहले विवादित कर के खिलाफ भुगतान किए गए करों का क्रेडिट घोषणाकर्ता को उपलब्ध होगा।
57.	ऐसे मामले जहां 22 जुलाई, 2024 तक अपील लंबित है, लेकिन विवादित कर मांगों का पूरा भुगतान घोषणा दाखिल करने से पहले ही किया जा चुका है। क्या ऐसे मामले डीटीवीएसवी योजना, 2024 का लाभ उठाने के पात्र हैं?	हां। डीटीवीएसवी योजना, 2024 की धारा 94 का संदर्भ लिया जा सकता है। उल्लिखित स्थिति स्पष्ट रूप से योजना की धारा 94(2) में शामिल है। तदनुसार, ऐसे मामले योजना के लिए पात्र होंगे।
टीडीएस से संबंधित प्रश्न		
58.	ऐसे मामलों में जहां कटौतीकर्ता ने अपनी अपील का निपटान कर दिया है, क्या टीडीएस कटौतीकर्ता को अधिनियम की धारा 201(1) के तहत अपने दायित्व से राहत मिलेगी। इसके अलावा, क्या टीडीएस कटौतीकर्ता को अधिनियम की धारा 40(क) के तहत व्यय कटौती का दावा करने की अनुमति दी जाएगी?	जहां कटौतीकर्ता ने अपनी कर देनदारी का निपटान कर दिया है, कटौतीकर्ता को देय ब्याज के अलावा उसकी देनदारी से राहत मिल जाती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 40 (क) के तहत व्यय कटौती के लिए अंतिम राहत ऐसे कटौतीकर्ता को उपलब्ध होगी
59.	क्या अधिनियम की धारा 200क (टीडीएस विवरणी के प्रसंस्करण पर सूचना के संबंध में) के तहत पारित सूचना के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर की गई अपीलों का निपटान डीटीवीएसवी योजना, 2024 के तहत किया जा सकता है?	हाँ, यदि धारा 200क के अंतर्गत सूचना के संबंध में अपील 22 जुलाई, 2024 तक लंबित है।

विविध		
60.	क्या नामित प्राधिकारी किसी भी पेटेंट संबंधी त्रुटि को सुधारने के लिए अपने आदेश में संशोधन कर सकता है?	हां, नामित प्राधिकारी किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के लिए धारा 92 के तहत अपने आदेश में संशोधन कर सकता है।
61.	जहां ऐसे प्राथमिक निर्धारिती के संबंध में अपील लंबित है, जो एक विदेशी इकाई है जिसकी भारत में पर्याप्त व्यावसायिक उपस्थिति नहीं है। क्या ऐसी विदेशी इकाई घोषणा दाखिल कर सकती है और भारत में मौजूद अपने प्रतिनिधि निर्धारिती के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर सकती है?	हां। उचित प्राधिकरण के साथ, एक प्रतिनिधि निर्धारिती योजना के तहत निपटान का विकल्प चुन सकता है। यहां तक कि मृत करदाता के मामले में भी, कानूनी प्रतिनिधि भी योजना के तहत निपटान का विकल्प चुन सकता है।
62.	यदि करदाता स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन के लिए डीटीवीएसवी योजना, 2024 का लाभ उठाता है, तो क्या अधिनियम की धारा 92गड़ के प्रावधान अलग से लागू होंगे?	हां, धारा 92गड़ के तहत द्वितीयक समायोजन लागू होगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 92गड़ में निहित द्वितीयक समायोजन का प्रावधान अप्रैल 2016 को या उससे पहले शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के संबंध में किए गए प्राथमिक समायोजन के लिए लागू नहीं है। इसका मतलब है कि, यदि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 या उससे पहले के मूल्यांकन वर्ष के लिए कोई प्राथमिक समायोजन है, तो यह अधिनियम की धारा 92गड़ के तहत माध्यमिक समायोजन के अधीन नहीं है।

(सुरबेंदु ठाकुर)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त मंत्री के विशेष कार्याधिकारी/वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव/वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
2. सचिव (राजस्व) के विशेष कार्याधिकारी
3. सीबीडीटी के अध्यक्ष और सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. सभी प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
5. सीबीडीटी के सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
7. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9. वेब मैनेजर, एडीजी (एस)-4, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. संयुक्त आयकर आयुक्त (डेटाबेस सेल) www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने के लिए